These amendments shall be deemed to have come into effect from 25.1.1995.

Sd/-
(S. J. GUNASEELAN)
Under Secretary
to the Govt. of India

o

The Manager
Government of India Press
Mayapuri
New Delhi.

Pay revision case of UDCs before Board of Arbitration

749. SHRI IQBAL SINGH:
SHRI MOHAMMED AFZAL
alias MEEM AFZAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3224 given in the Rajya Sabha on the 18 August, 1994 and state:

(a) whether the Board of Arbitration have submitted its Award to Government with regard to the revision of pay scale of Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service from Rs. 1200—2040 to Rs. 1400—2600;

(b) if so, what are the full details in this regard;

(c) if not, the reasons for not submitting the aforesaid Award in the interest of the Upper Division Clerk category: and

(d) by when it is likely to be implemented by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Board of Arbitration heard the matter in June, 1994, September, 1994 ond Mrch, 1995 it hs to conclude the haering and give its award.

(d) Does not arise.

सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण

750. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में विस्तृत योजनायें/कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) वित्त वर्ष 1995–96 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं तथा अन्य संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी तथा अन्य चुनिन्दा अकादमियों संस्थानों में तथा केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली में प्रवेश प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है। तथापि, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारीयों/ कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों पर आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कुल मिलाकर 107 कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1995–96 के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं के क्षेत्रों से संबंधित विशेष विषयों में भी 128 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोजित किए जाने हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों और बैंकों के कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार केन्द्र तथा राज्य सरकार तथा साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के तहत प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों की दक्षता को बढ़ाने के लिए 19 शेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) जबकि, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक समस्त बजट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित करने वाले अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानक शुल्क का भुगतान किया जाता है चाहे प्रशिक्षार्थियों की संख्या अथवा संयोजन कैसा भी हो क्योंकि यह प्रत्येक कार्यक्रम में बदलता रहता है।

Penal for filling vacancies through Direct Recruitment

751. SHRI RAGHAVJI:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of India recruitment rules and procedures provide that the size of the panel for filling vacancies through direct recruitment must conform to the number of advertised vacancies or to the number of vacancies available for filling at the time of selection;

(b) if so, whether it is also a fact that a reserve panelist cannnot be offered appointment if the advertised/available vacancies have been filled by main panelists; and

(c) if so, what is the procedure for dealing with blatant violations of the above provisions?

THE MINISTER OF STATE I THE MINISTRY OF PERSONNE PUBLIC GRIEVANCES AND PEN SIONS (SMT. MARGARET ALVA (a) As per the existing instructic the size of the panel should be e to firm number of vacancies.

(b) Yes Sir, However in the ev where a vacancy is created by selected candidate resigning the po or in the event of his death with six months from the date of his joi ing it can be filled by the reserv panelist.

(c) It is the responsibility of th Ministries/Departments to impleme the instructions. Instrutions ha also been issued enjoining upon th Government servants that they shou faithfully implement the laid dow policies, rules and regulations etc. service matters If any violatio come to the notice of this departme then appropriate action is taken rectify the situation.

Maternity Benefits

752. SHRI J. S. RAJU:
SHRI N. GIRI PRASAD.

Will the PRIME MINISTER pleased to state:

(a) whether it is a fact that th Central Governmen women em loyees are entitled to maternit benefits only if there are not mo than two living children or they ha not delivered more than twice earlie and

(b) if so, whether women wh have delivered once but twice w are surviving, are deprived of th beefits while delivering secon time?

THE MINISTER OF STATE I THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PEN SIONS (SMT. MARGARET ALVA) (a) and (b) As per the provisions o